REF ID	:	BSC/Q0301
NSQF LEVEL	:	1.0
Version No.	:	3

Qualification Pack (QP) Parameters

Sector	BFSI
Sub-Sector	BANKING
Occupation	FINANCIAL INCLUSION SERVICES

Vocational/Skill Development Course

Course Title- Business Correspondent/Business Facilator (Part-1)

व्यवसाय संवाददाता (बीसी) के बारे में संक्षिप्त जानकारी

व्यवसाय संवाददाता (बीसी) एनजीओ जैसे व्यक्ति या निकाय हैं जो बैंकों के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।

व्यवसाय संवाददाता बैंक प्रतिनिधि होते हैं। वे ग्रामीणों को बैंक खाते खोलने में मदद करते हैं। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को प्रत्येक नया खाता खोलने, उनके माध्यम से किए गए प्रत्येक लेनदेन, संसाधित किए गए प्रत्येक ऋण-आवेदन आदि के लिए बैंक से कमीशन मिलता है। बीसी अपने साथ उपकरण रखते हैं ताकि वे ग्रामीणों से अंगूठे के निशान, डिजिटल हस्ताक्षर आदि ले सकें। इन उपकरणों में मोबाइल फोन, माइक्रो एटीएम, रसीद जनरेटर आदि शामिल हैं। (पैसा जमा करें, बचत खाते, ऋण आदि से पैसा निकालें)। ग्रामीण अपना अंगूठा निशान या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर देता है, और पैसा प्राप्त कर लेता है। बिजनस कॉरेस्पॉन्डेंट खुद बैंक की तरह काम करते हैं। वे डिपॉजिट लेते हैं और बैंक की ओर से छोटे लोन भी दे सकते हैं। बिजनस कॉरेस्पॉन्डेंट माइक्रो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड प्रॉडक्ट्स और पेंशन प्रॉडक्ट्स भी बेचते हैं।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) की भूमिका

भारत की ग्रामीण आबादी अभी भी महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं की कमी का सामना कर रही है। 2012 के ग्लोबल फाइंडेक्स सर्वे के अनुसार, लगभग 650 मिलियन लोगों को अभी भी "अंडरबैंक्ड" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस समस्या से निपटने के लिए आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने 2006 में एक विनियमन बनाया। यह बैंकों को लोगों की मदद के लिए तीसरे पक्ष और गैर-बैंकिंग एजेंटों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

इस तृतीय-पक्ष एजेंट को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के रूप में जाना जाता है। बीसी समाज के आर्थिक या डिजिटल रूप से कमजोर सदस्यों को आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। यह उन ग्रामीण लोगों की मदद करता है जो अशिक्षित और कम जागरूक हैं।

बिजनस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल

2006 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिजनस कॉरेस्पॉन्डेट या बिजनस फैसिलिटेटर्स जैसे नॉन बैंक इंटरमीडियरीज इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इसका मकसद उन इलाकों तक बैंकिंग और दूसरी फाइनैंशल सर्विसेस का दायरा बढ़ाना था, जहां बैंकों के ब्रांच नहीं हैं। आरबीआई इसके जरिए फाइनैंशल इनक्लूजन अभियान को आगे बढ़ा रहा है।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल कमीशन मॉडल के आधार पर काम करता है। बैंक उन्हें उनके काम के बदले अच्छी बढ़ोतरी देते हैं। उदाहरण के लिए, एक बीसी को बैंक खाता खोलने, धन हस्तांतरित करने या नए ऋण वितरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। सेवाओं में कमी की स्थिति में निर्धारित कमीशन का कुछ प्रतिशत रोका या वापस लिया जा सकता है।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल का लाभ

बीसी मॉडल बैंकों को समाज के कमजोर वर्ग तक पहुंचने में मदद करता है। पारंपरिक बैंक स्वतंत्र रूप से कमजोर वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। बीसी पारंपरिक बैंकों की तुलना में व्यापक श्रेणी की बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, छोटे ऋण, धन हस्तांतरण और बिल भुगतान सभी बीसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

बीसी की मदद से वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सकता है. यह उन लोगों को सेवाएं प्रदान करता है जो खराब डिजिटल ज्ञान, जागरूकता की कमी और विश्वास के मुद्दों के कारण पारंपरिक बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

यदि आप मध्यस्थ के व्यवसाय में हैं तो संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। लेखन और संचार में कौशल रखने वाला व्यक्ति बीसी बन सकता है। बिजनेस में रुचि रखने वाला व्यक्ति यह काम अधिक आसानी से कर सकता है।

बीसी के रूप में काम करने के लिए, आपके पास पत्रकारिता, व्यवसाय या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जिन लोगों को वित्तीय उद्योग की समझ है या उन्होंने बिजनेस पत्रकार के रूप में काम किया है, वे बीसी बन सकते हैं।

जो लोग बीसी बनने के इच्छुक हैं उन्हें बिजनेस समाचार लिखना और पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यदि आपने एक बिजनेस पत्रकार के रूप में काम किया है, तो यह आपके सीवी को बढ़ावा देगा। एक बार जब आप सभी आवश्यक कौशल प्राप्त कर लेते हैं, तो आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कौन बन सकता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट?

भारतीय रिजर्व बैंक ने कई इकाइयों को बैंकों के बिजनस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम करने की इजाजत दी है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बीसी के लिए पात्रता मानदंड नीचे उल्लिखित हैं।

- पूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, डाकघर कर्मियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को बीसी में शामिल होने की अनुमति है।
- किराना, मेडिकल दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों से व्यक्ति बीसी बन सकते हैं।
- सोसायटीएमएफआई बीसी बन सकते हैं।/ट्रस्ट अधिनियम के तहत स्थापित एनजीओ/
- राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत समितियां बीसी बन सकती हैं। पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार पंजीकृत समितियाँ।
- भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं के एजेंट। बीमा कंपनियाँ और व्यक्ति जिनके पास पेट्रोल पंप हैं।
- धारा 25 कंपनियां जो स्वतंत्र संगठन हैं या जिनमें बैंक, एनबीएफसी, टेलीकॉम कंपनियां और अन्य कॉर्पोरेट निकाय या उनकी होल्डिंग कंपनियों की 10 प्रतिशत से अधिक उचित हिस्सेदारी नहीं है।
- बैंक सीएससी ऑपरेटरों सहित किसी भी व्यक्ति को बीसी के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- बैंकों से जुड़े एक अच्छी तरह से संचालित स्वयं सहायता समूह के अधिकारी (एसएचजी), जमा न लेने वाली एनबीएफसी बीसी बन सकते हैं। (बैंकिंग वित्त कंपनियां-गैर)

व्यवसाय संवाददाताओं की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

1. नए ग्राहक लाना

बीसी का मुख्य कर्तव्य ग्राहकों का मार्गदर्शन करना है ताकि वे छोटे ऋण लें। बीसी लक्षित ग्राहकों को धन के प्रबंधन के बारे में सलाह देता है, शिक्षित करता है और सलाह देता है।

2. उत्पाद और सेवाएँ वितरित करना

बीसी विभिन्न वित्तीय उत्पादों में ग्राहकों के नामांकन की जाँच करता है। यह विभिन्न जमा प्रपत्रों की प्रारंभिक प्रक्रिया का प्रबंधन करता है जिसमें प्राथमिक डेटा का सत्यापन शामिल है।

3. भुगतान और संग्रहण

बीसी का दूसरा कर्तव्य धन संग्रह करना और भुगतान करना है। उदाहरण के लिए, छोटे मूल्य की जमा और नकद निकासी (अधिकतम मूल्य- ₹20,000/- प्रति खाता प्रति दिन) बीसी द्वारा नियंत्रित की जाती है। न्यूनतम मूल्य के मामले में कोई निश्चित सीमा नहीं है।

व्यवसाय संवाददाताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा

- बीसी संभावित ग्राहकों की पहचान करता है।
- केवाईसी बीसी द्वारा पूरा किया जाएगा.
- बीसी आवेदन भरने, खाते खोलने और उन्हें बैंक में जमा करने की प्रक्रिया पूरी करता है।
- यह नोफ्रिल जमा खाते खोलता है-
- यह छोटे मूल्य की जमा और निकासी एकत्र करता है और भुगतान करता हैशून्य :न्यूनतम :, अधिकतम :₹2000/- प्रति लेनदेन।
- आईडीबीआई बैंक की एफआई योजना के अनुसार, यह छोटे मूल्य के प्रेषण को कवर करता है।
- बीसी और उसके एजेंट को अपने कार्यस्थल पर या किसी भी सुविधाजनक स्थान पर प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा प्रत्येक) मामले में₹2000/-) तक नकद स्वीकारवितरित/ करने का अधिकार है।
- यह उचित प्राधिकारी के साथ बैंक की ओर से किसी अन्य बैंक सेवाओं को अधिकृत कर सकता है।
- 3 महीने के लिए मिनी खाते के विवरण और खाते की अन्य जानकारी ठीक करना।
- जब उन्हें ऐसा करने का काम सौंपा जाता है तो यह वित्तीय उत्पादों को क्रॉससेल कर सकते हैं।- इन उत्पादों में पेंशन उत्पाद, म्यूचुअल फंड उत्पाद और अन्य तृतीयपक्ष उत्पाद शामिल हैं।-
- यदि सीएससी के उपएजेंट शामिल हैं तो बीसी को प्-रतिष्ठा संबंधी जोखिमों का ध्यान रखना चाहिए।

बीसी की नियुक्ति

- उस क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसमें वे काम करना प्रस्तावित करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से स्थापित होना चाहिए, अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और स्थानीय लोगों का उन पर भरोसा होना चाहिए।

- बीसी की पीओएस मशीनों और अन्य उपकरणों में निवेश करने की क्षमता। बीसीएस के रूप में चयनित व्यक्तियों के मामले में, मानदंड इस प्रकार हैन्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास। : निवास और व्यवहार आदि के सत्यापन के लिए फील्ड जांचआरसीयू आयोजित की जाएगी।/
- विश्वसनीयता जांच - किसी अन्य बैंक में खाता। बैंक में खाता खोलना चाहिए (आधार शाखा)
- व्यवसाय की मात्रा के आधार पर सुरक्षा जमाबैंक गारंटी की उपयुक्त राशि।/

व्यवसाय संवाददाता का कार्य

उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. उनके कार्यों में शामिल हैं

- उधारकर्ताओं की पहचान करें
- छोटे मूल्य की जमाराशियाँ एकत्रित करना
- छोटे मूल्य के ऋण का वितरण
- ब्याज की वसूलीमूलधन की वसूली/
- उत्पादों और बचत के बारे में जागरूकता बढ़ाना

वित्तीय समावेशन क्या है?

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य सभी व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने के प्रयासों से है, चाहे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति या कंपनी का आकार कुछ भी हो। वित्तीय समावेशन उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है जो लोगों को वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन सेवाओं का उपयोग करने से रोकती हैं। इसे समावेशी वित्त भी कहा जाता है।

वित्तीय समावेशन का महत्व

वित्तीय समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है इसके बहुत व्यापक और सामान्य कारण हैं। कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

वित्तीय समावेशन से गरीबी और असमानता कम होती है। वित्तीय समावेशन हाशिए पर रहने वाले और कम आय वाले व्यक्तियों को बचत, ऋण और बीमा जैसी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के अवसर प्रदान करता है। उन्हें अपने वित्त का प्रबंधन करने और आयसृजन गतिविधियों में निवेश करने के लिए उपकरणों के साथ स-शक्त बनाकर, वित्तीय समावेशन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है।

- **वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है ।**

  एक सामान्य तर्क यह है कि जब अधिक लोगों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होगी, तो वे अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। वित्तीय समावेशन बढ़ने से बचत, निवेश और उद्यमशीलता का उच्च स्तर बढ़ता है, जिससे स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं दोनों में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- **वित्तीय समावेशन छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देता है ।**

  छोटे व्यवसायों को अक्सर पारंपरिक बैंकिंग स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नवीन ऋण मॉडल और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वित्तीय समावेशन उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक धन उपलब्ध करा सकता है।
- **वित्तीय समावेशन अन्यथा हाशिए पर मौजूद जनसांख्यिकी को सशक्त बनाता है।**

  उदाहरण के लिए, महिलाओं पर लक्षित वित्तीय समावेशन पहल लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके, महिलाओं को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है, जिससे शैक्षिक अवसरों में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और घरों के भीतर निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि हो सकती है।
- **वित्तीय समावेशन नवाचार को बढ़ावा देता है।**

  वित्तीय समावेशन वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे नई प्रौद्योगिकियों और फिनटेक समाधानों का विकास होता है जो वंचित आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये नवाचार व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचा सकते हैं और वित्तीय सेवाओं में प्रगति ला सकते हैं।
- **वित्तीय समावेशन डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे सकता है।**

  चूंकि प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना भी डिजिटल समावेशन में योगदान देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिक लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें।

बैंक से आप क्या समझते हैं?

एक बैंक को एक वित्तीय संस्थान के रूप में जाना जाता है जो जनता से जमा स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार होता है और अपने उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के साथ जमा भी बनाता साथ मांग-है। बैंक ये ऋण देने की गतिविधियाँ सीधे या पूंजी बाज़ार के माध्यम से कर सकते हैं ।

बीआर अधिनियम, धारा 5 (सीके अनुसार (, "एक बैंकिंग संस्थान एक कंपनी है जो भारत में बैंकिंग का कारोबार करती है।"

बीआर अधिनियम की धारा 5 (बी) में बैंकिंग व्यवसाय का वर्णन "उधार देने या निवेश के उद्देश्य से जनता से जमा राशि को स्वीकार करना, मांग पर या अन्यथा चुकाना और चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर द्वारा निकासी, या अन्यथा" के रूप में किया गया है।

भारत में बैंकों के प्रकार

भारत में बैंकों को सेंट्रल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विशिष्ट और सहकारी बैंक में वर्गीकृत किया गया है। हमने निम्नलिखित अनुभाग में भारत में बैंकों के प्रकार और उनके संबंधित अर्थों पर चर्चा की है।

प्रकार	अर्थ
केंद्रीय अधिकोष	• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) देश का केंद्रीय बैंक है। • यह अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी और विनियमन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। • यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। • आरबीआई वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वाणिज्यिक बैंक	• यह आम जनता के लिए जमा स्वीकार करने औरया ऋण देने के/ संबंध में कार्य करता है। • ऐसे बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण को निवेश के रूप में उपयोग करते हैं। • देश में कुछ वाणिज्यिक बैंक एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आदि हैं।
विशिष्ट बैंक	• इन बैंकों का गठन किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र की पूर्ति के एकमात्र उद्देश्य से किया जाता है। • वे आयात और निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या देश के विशिष्ट क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। • EXIM बैंक एक विशेष बैंक का सबसे अच्छा उदाहरण है।
सहकारी बैंक	• ये बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं। • वे सहकारी बैंकों के सदस्यों को आसान ऋण प्रदान करते हैं। • सहकारी बैंकों की बुनियादी गतिविधियों में से एक वंचित आबादी को वित्तीय संसाधन प्रदान करना है। • न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक आदि भारत में सहकारी बैंकों के उदाहरण हैं।

भारत में वाणिज्यिक बैंक के प्रकार

भारत में वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है:

प्रकार	अर्थ
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	• जिन वाणिज्यिक बैंकों में सरकार के पास अधिकांश शेयर)50% से अधिकहोते हैं (, वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। • पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उदाहरण हैं
निजी क्षेत्र के बैंक	• जिन वाणिज्यिक बैंकों में व्यक्तिगत शेयरधारकों के पास अधिक इक्विटी हिस्सेदारी होती है, उन्हें निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। • इन बैंकों के कार्य और गतिविधियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समान हैं। • कुछ पहलू जैसे कि लगाए गए शुल्क, निजी क्षेत्र के बैंक की सेवाओं की अवधि और विवरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भिन्न होते हैं। • एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आदि भारत में सबसे प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के बैंक हैं।

लघु वित्त बैंक	• इन बैंकों का लक्ष्य देश में वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना है। • ऐसे बैंकों में छोटी और सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयाँ, असंगठित क्षेत्र की विभिन्न संस्थाएँ, सीमांत कारीगर और छोटे किसान आदि भी शामिल हैं। • जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक देश के कुछ छोटे वित्त बैंक हैं।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	• इन बैंकों के पास छोटे किसानों और सीमांत श्रमिकों, कृषि मजदूरों, छोटे उद्यमियों, कारीगरों आदि को ऋण प्रदान करने जैसे काफी विशिष्ट जनादेश हैं। • ऐसे बैंक ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के बाद स्थापित किए गए हैं। • भारत में कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक इत्यादि हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न कार्यों में शामिल हैं:

अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करना वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख कार्यों में से एक है। ये जमाएँ व्यक्तियों और व्यावसायिक संगठनों दोनों से स्वीकार की जा सकती हैं। बचत जमा, सावधि जमा और चालू जमा ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों में धन जमा किया जा सकता है।

ऋण प्रदान करना वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जाने वाली एक अन्य गतिविधि है। ये वही फंड हैं जो बैंक को जमा के माध्यम से प्राप्त हुए थे। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन का उपयोग करके और उसे ऋण में निवेश करके मुनाफा कमाते हैं। हालाँकि, ऋण देना विभिन्न प्रकार का हो सकता है जैसे नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, बिलों में छूट, अग्रिम आदि।

फंड रेमिटेंस या मनी ट्रांसफर भी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। निर्दिष्ट कमीशन के अनुसार धनराशि को विभिन्न तरीकों जैसे एनईएफटी, ड्राफ्ट पे ऑर्डर, आईएमपीएस, आरटीजीएस आदि के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है।

चेक जारी करना वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को धन निकालने में मदद करने के लिए किया जाता है। चेक का उपयोग करके, ग्राहक अपने स्वयं के उपयोग के लिए या भुगतानकर्ता के लिए पैसे निकाल सकते हैं। चेक या तो वाहक हो सकता है या रेखांकित किया जा सकता है। जबकि एक वाहक चेक को काउंटर पर भुनाया जा सकता है, एक रेखांकित चेक केवल भुगतानकर्ता के खाते में जमा किया जा सकता है।

सामान्य उपयोगिताएँ भी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनमें ट्रैवलर चेक जारी करना, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा, सुरक्षित अभिरक्षा के लिए लॉकर सुविधा आदि शामिल हैं।

एक एजेंट के रूप में सेवाओं में चेक का संग्रह, बीमा प्रीमियम भुगतान, ड्राफ्ट और बिल, ट्रस्टी या निष्पादक या ग्राहकों की संपत्ति आदि शामिल हैं।

ई-बैंकिंग

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, या ई-बैंकिंग में ग्राहकों को अपने बैंक खातों और निधियों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग शामिल है। ई-बैंकिंग का मुख्य लाभ यह है कि इससे ग्राहकों को लेनदेन के लिए बार-बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

इंटरनेट की आसान उपलब्धता के साथ, ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना बहुत त्वरित और सुविधाजनक हो गया है। परेशानी मुक्त पहुंच के कारण ई-बैंकिंग बैंकरों और ग्राहकों दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है। बैंकों को अतिरिक्त लेनदेन लागत वहन करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें मानवीय त्रुटि की भी काफी कम गुंजाइश है। निर्धारित लागत भी काफी कम हो जाती है।

जहां तक ग्राहकों का सवाल है, वे चौबीसों घंटे सुविधा का आनंद लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक लेनदेन के लिए बैंक परिसर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, यह ग्राहक के लिए समय, पैसा और प्रयास बचाने में मदद करता है। डिजिटल बैंकिंग कुछ लेनदेन के मामले में भौगोलिक बाधाओं को भी दूर करती है।

ई-बैंकिंग के रूप

ई-बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं:

प्रकार	अर्थ
अंतराजाल लेन देन -	• यह इंटरनेट पर वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन की सुविधा देता-है। • ग्राहक असंख्य लेनदेन कर सकते हैं जैसे धन भेजना, उपयोगिता बिलों का भुगतान करना, शेष राशि की जांच करना आदि।
एटीएम	• स्वचालित टेलर मशीन एक कंप्यूटरआधारित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ग्राहकों को धन निकालने-, धन जमा करने और पिन बदलने में (व्यक्तिगत पहचान संख्या) सक्षम बनाती है। • एटीएम के आगमन के साथ, ग्राहकों को ऐसी बैंकिंग गतिविधियों के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है।
मोबाइल बैंकिंग	• यह ग्राहकों को अपने स्मार्टफ़ोन पर बैंक के ऐप के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। • यह इंटरनेट बैंकिंग के समान है। • बैंक का ऐप एंड्रॉइड या आईओएस प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है और इसका उपयोग असंख्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
डेबिट कार्ड	• डेबिट कार्ड ग्राहकों को कई कारणों से सीधे अपने बैंक खाते से धनराशि निकालने की अनुमति देता है। • लेनदेन की राशि सीधे ग्राहकों के बैंक खाते से काट ली जाती है। • डेबिट कार्ड का उपयोग प्वाइंट ऑफ सेल भुगतान करने आउटलेट पर (पीओएस), ऑनलाइन शॉपिंग करने और एटीएम से धनराशि निकालने के लिए किया जा सकता है।

बैंक खाते और उनकी विशेषताएं

जब बैंकिंग की बुनियादी बातों की बात आती है, तो विभिन्न प्रकार के बैंक खातों और उनकी विशेषताओं के बारे में सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के बैंक खाते हैं:

प्रकार	विशेषताएँ
बचत खाता	• वे भविष्य की बचत के लिए हैं। • बचत खातों का मुख्य उद्देश्य आम जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है। • बचत बैंक खाते में जमा की जाने वाली संख्या और राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। • इस खाते में बकाया क्रेडिट राशि पर बैंक के मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार ब्याज मिल सकता है।
चालू खाता	• ये खाते व्यवसायियों, कॉर्पोरेट निकायों, व्यापारियों आदि द्वारा खोले गए सक्रिय खाते हैं। • व्यवसाय के संबंध में धन की कई प्राप्तियों और भुगतानों के कारण चालू खाते को समयसमय पर - संचालित किया जा सकता है। • जमा और निकासी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
सावधि जमा खाता	• यह एक निश्चित अवधि के लिए जमा और निकासी नोटिस के अधीन जमा दोनों को समाहित करता है। • सावधि जमा, जमा के समय तय की गई पूर्व निर्धारित अवधि के बाद पारिश्रमिक योग्य सावधि जमा हैं। • कॉल जमा को मांग या सावधि देनदारियों के रूप में माना जा सकता है, जो ऐसी जमा स्वीकार करते समय सहमत पुनर्भुगतान की शर्तों और निकासी की सूचना के अधीन है। • वे हस्तांतरणीय नहीं हैं.
आवर्ती जमा खाता	• ग्राहक एक मानक पैटर्न में 6 महीने से 120 महीने तक की अवधि के लिए मासिक किस्तों पर एक विशेष राशि भेजते हैं। • अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ब्याज सहित पूरी राशि देय है। • आवर्ती जमा खाते मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। • जमा की समयावधि 6 माह से 10 वर्ष तक होती है। • आरडी खाते में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि 500 रुपये प्रति माह और उसके बाद 100 रुपये के गुणक में है।

बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएँ

उपरोक्त के अलावा, भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ अन्य सेवाएँ हैं:

लॉकर सुविधा

- यह एक ऐडऑन है जो वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके आभूषण-, शेयर, डिबेंचर और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान करते हैं।
- यह घरों या अन्य जगहों पर चोरी के कारण कीमती सामान चोरी होने के जोखिम को कम करता है।

म्यूचुअल फंड्स

- यह एक निवेश प्रक्रिया है जिसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड, स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियों जैसी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए विभिन्न निवेशकों से एकत्र किए गए धन का एक पूल शामिल है।

बैंकएश्योरेंस

- बैंकएश्योरेंस एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक समझौता है जो बीमा कंपनी को बैंक के ग्राहकों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने औरया/ बेचने की अनुमति देता है।
- इस तरह की साझेदारी का समाधान बैंक और बीमा कंपनी दोनों के लिए लाभदायक है।

अंतराजाल लेन - देन

- यह किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट या ऐप से विभिन्न प्रकार के वित्तीय संचालन करने में (देन-लेन)सक्षम बनाता है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड

- एक बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जारी करता है। हालाँकि, जो ग्राहक क्रेडिट कार्ड चुनना चाहते हैं, वे अपने संबंधित बैंक में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक भुगतान कार्ड है जो खरीदारी करते समय हार्ड कैश मनी की जगह ले सकता है। यह एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, लेकिन लेनदेन करते समय डेबिट कार्ड में मौजूद पैसा सीधे ग्राहक के बैंक खाते से निकाल लिया जाता है।
- क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो ग्राहक को क्रेडिट लाइन के विरुद्ध धन का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसे कार्ड की क्रेडिट सीमा भी कहा जाता है।

चेक और डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

- चेक एक कागजी दस्तावेज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का आदेश देता है जिसका नाम चेक पर उल्लिखित है।
- डिमांड ड्राफ्ट विनिमय बिल की तरह ही एक समझौता योग्य दस्तावेज है।
- एक बैंक द्वारा एक ग्राहक को एक डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है (आदाता), जिसमें दूसरे बैंक या उसकी (आदाता) को एक निश्चित राशि का भुगतान (भुगतानकर्ता) अपनी शाखाओं में से किसी एक को निर्दिष्ट पार्टी करने के लिए कहा जाता है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो (repo) का अर्थ है– पुनर्खरीद विकल्प अथवा पुनर्खरीद समझौता। यह अल्पावधि यानी कम समय के उधार का ही एक रूप है। यह बैंकों/वित्तीय संस्थानों (banks/financial institutions) को सरकारी सिक्योरिटीज (financial securities) के खिलाफ अन्य बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से पैसे उधार लेने की इजाजत देता है। इसके तहत सिक्योरिटीज (securities) को निश्चित समयावधि के बाद एवं पूर्व निर्धारित मूल्य (pre determined price) पर वापस खरीदने के लिए एक समझौता होता है। यह बैंकों द्वारा अल्पकालिक पूंजी (short term capital) जुटाने का एक सुरक्षित तरीका safe (method) माना जाता है।

रेपो रेट (repo rate) ही वह ब्याज दर (interest rate) है, जिस पर देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया (reserve Bank of India) अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार पर देता है। जब भी वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसे की कमी होती है तो वे केंद्रीय बैंक से पैसा उधार पर लेते हैं, जिसे रेपो रेट के अनुसार चुकाया जाता है

सरकार रेपो रेट में इजाफा तब करती है, जब उसे कीमतों (price) को नियंत्रित (control) करने एवं उधार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है।

वहीं, वह रेपो रेट में कमी तब करती है, जब उसे बाजार (market) में अधिक धन पहुंचाने एवं आर्थिक विकास (economic development) का समर्थन (support) करने की आवश्यकता होती है।

रिवर्स रेपो रेट क्या है?

रिवर्स रिपो रेट वह दर है, जो किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्यिक बैंकों को उसके पास उनके अतिरिक्त धन को पार्क करने के लिए भुगतान करता है। यह भी एक मौद्रिक नीति यानी मानिटरी पालिसी है। इसका इस्तेमाल देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया यानी आरबीआई बाजार में धन के प्रवाह (flow of cash) को विनियमित/नियंत्रित करने के लिए करता है। जब भी आवश्यकता होती है, आरबीआई कामर्शियल बैंकों से उधार लेता है एवं उन्हें लागू रिवर्स रेपो रेट के अनुसार ब्याज का भुगतान करता है। एक नियत समय पर आरबीआई की ओर से प्रदान किया जाने वाला रिवर्स रेपो रेट आम तौर पर रेपो रेट से कम होता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उसके पास जमा करने एवं रिटर्न अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन देने को रिवर्स रेपो रेट में इजाफा करता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है. बाजार में जब भी बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी धनराशि उसके पास जमा करा दें।

सीआरआर–कैश रिजर्व रेशियो क्या है?

भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उनकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर के रूप में जाना जाता है। नकद आरक्षित अनुपात के रूप में रखी गई राशि या तो आरबीआई को भेजा जाता है या बैंक की तिजोरी में रखा जाता है।

सीआरआर बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपयोगी साधन है।

सरल शब्दों में सीआरआर या नकद आरक्षित अनुपात नकदी का प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपनी कुल डिपॉजिट की तुलना में रिजर्व में रखना होता है, जिसे तकनीकी रूप से 'शुद्ध मांग और समय देयता' (एनडीटीएल – नेट डिमांड ऐंड टाइम लायबिलिटीज) कहा जाता है।

सीआरआर दर में बदलाव करके आरबीआई मुद्रास्फीति को अपने वांछित स्तर पर रखने और बैंकिंग प्रणाली में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित और मॉनिटर करता है।

एसएलआर क्या है?

SLR का फुल फॉर्म होता है—Statutory liquidity ratio, जिसका मतलब यानी हिन्दी में अर्थ होता है— वैधानिक तरलता अनुपात। यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है, जोकि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। यह नकदी (cash), स्वर्ण भंडार (gold reserves), सरकारी प्रतिभूतियों (government approved securities) वगैरह किसी भी रूप में हो सकता है। जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं, उसके बाद ही उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। यह अनुपात (Statutory liquidity ratio) कितना होगा, इसका निर्धारण रिजर्व बैंक करता है।

रिजर्व बैंक के प्रावधानों के मुताबिक, हर कॉमर्शियल बैंक को अपने रोजाना का कारोबार बंद होने के बाद अपनी शुद्ध मांग जमाओं (Net Demand). और सामयिक उत्तरदायिता (Time Liabilities) का एक निश्चित हिस्सा तरल परिसंपत्तियों (liquid assets) के रूप में सुरक्षित कर लेना अनिवार्य होता है। यह तरल परिसंपत्तियां cash, gold और unencumbered approved securities के रूप में हो सकती हैं। बैंक की कुल demand and time liabilities के प्रति इन सुरक्षित रखे जाने वाले liquid assets का जो भी अनुपात होता है, उसे Statutory Liquidity Ratio (SLR) या वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं।

एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई द्वारा संचालित IMPS (आईएमपीएस) के बारे में बताइये।

NPCI का फुल फार्म National Payment Corporation Of India है एनपीसीआई का हिंदी अर्थ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है देश मे पेमेंट नेटवर्क का काम करती है NPCI के द्वारा ही बैंकिंग पेमेंट सिस्टम लेन-देन प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है शुरूआत मे NPCI को आरबीआई द्वारा प्रमोट किया गया था आज के समय मे लगभग सभी भारतीय बैंक NPCI से जुड़ चुके है NPCI द्वारा कई प्रकार की सर्विसेस दी जाती हैं।

IMPS सर्विस एनपीसीआई ने ही बनाया है और इसे एनपीसीआई की देखरेख मे संचालित किया जाता है इसका फुल फार्म Immediate Payment Service (तत्काल भुगतान सेवा) है। आईएमपीएस का उपयोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट मे पैसे ट्रांसफर के लिए करते है आईएमपीएस सेवा एनपीसीआई के तरफ से चौबीस घंटे दी जाती है आईएमपीएस के जरिए तत्काल सामने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट मे पैसे पहुँच जाता है, आईएमपीएस के जरिए दो तरीको से पैसे ट्रांसफर किये

- अकाउंट नंबर + आईएफएससी कोड के जरिए IMPS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किये जा सकते है।
- एमएमआईडी + मोबाइल नंबर के द्वारा IMPS के माध्यम से पैसे उसके अकाउंट मे भेजे जा सकते है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना क्या है?

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। Direct Benefit Transfer का उद्देश्य सीधे लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करना है। भारत सरकार ने क्रेडिट ट्रांसफर में लीकेज और देरी को कम करने के लिए Direct Benefit Transfer की यह योजना शुरू की। सरकार का उद्देश्य उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को लाभ पहुंचाना है, जो केंद्रीय योजनाओं के तहत हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले सब्सिडी लाभ को चेक जारी करने, नकद भुगतान या सेवाओं अथवा वस्तुओं पर कीमत छूट प्रदान करने की बजाय सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित यानी जमा करने का काम किया जाता है।

UPI (यूपीआई) क्या है?

UPI का फूल फार्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यह सर्विस भी एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है यूपीआई के जरिए भी तुरंत किसी के अकाउंट मे पैसे भेजे जाते हैं।

यूपीआई के जरिए तीन तरीको से पेमेंट कर सकते है–

1. जो की एक ईमेल एड्रेस की तरह होता है अगर सामने वाले व्यक्ति के UPI ID पता है तो इंटर करके पैसे ट्रांसफर किया जा सकते है।
2. अकाउंट नंबर + आईएफएससी कोड डालकर यूपीआई के माध्यम से पैसे भेज सकते है।
3. QR कोड स्कैनिंग करके अकाउंट मे तुरंत पैसे भेज सकते है।

RUPAY (रूपे कार्ड) क्या है?

रूपे कार्ड भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। रूपे कार्ड से देश के सभी पीओएस डिवाइसेज और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान किया जा सकता है और एटीएम से कैश निकाला जा सकता है। यह भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। रूपे कार्ड को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम (NPCI) ने विकसित किया है | इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग के लिए प्रवर्तित किया है। मौजूदा समय में रूपे ग्लोबल काड्र्स पांच वेरिएंट्स में जारी किए जाते हैं रूपे क्लासिकल कार्ड, रूपे क्लासिक क्रेडिट कार्ड, रूपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, रूपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और रूपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड ।

रुपे (अंग्रेज़ी: RuPay) भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली नेटवर्क है। इसका उपयोग क्रेडिट, डेबिट और प्रीपैड कार्ड द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन करने में किया जाता है। भारत के अलावा यह कई अन्य देशों में भी उपलब्ध है। कई कंपनियों के साथ कार्ड के समझौते के कारण इसका इस्तेमाल कई अन्य नेटवर्क के साथ भी किया जा सकता है।